भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4519
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

एमटीएनएल का पुनरुद्धार पैकेज

4519. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) एमटीएनएल की निरंतर वित्तीय संकट की स्थिति को देखते हुए 6,000 करोड़ रूपये का पुनरुद्धार पैकेज एक अनंतिम राहतोपाय के रूप में इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता को किस प्रकार सुनिश्चित करेगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर वर्ष 2019 से कई पुनरुद्धार पैकेज देने के बाद, एमटीएनएल के घाटे से मुनाफे में पूर्ण वित्तीय परिवर्तन के बारे में कोई समयबद्ध रूपरेखा या श्वेत पत्र जारी किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2023-24 के पुनरुद्धार पैकेज के अनुमोदन के बाद इस संबंध में कोई मापनीय प्रदर्शन मानक निधर्धारित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एमटीएनएल तथा बीएसएनएल द्वारा सार्वजनिक व्यय के संबंध में जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है;

(घ) सरकार कर्मचारी लागत, अक्षम अवसंरचना और घटते राजस्व जैसे पुराने मुद्दों को हल किए बिना एमटीएनएल में बार-बार वित्तीय निवेश को किस प्रकार उचित ठहराएगी;

(ङ) एमटीएनएल की परिसंपत्ति के मौद्रीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और पुनरुद्धार योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना वास्तविक राजस्व सृजित किया गया है; और

(च) एमटीएनएल का दैनिक संचालन बीएसएनएल को सौंप दिए जाने के बाद सरकार द्वारा एमटीएनएल की पहचान, कार्यबल और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) सरकार ने बीएसएनएल/एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- वर्ष 2019 में लगभग 69 हज़ार करोड़ रुपये की राशि प्रथम पुनरुद्धार पैकेज दिया गया, जिससे बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रचालन लागत कम हुई।
- वर्ष 2022 में लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये की राशि का पुनरुद्धार पैकेज दिया गया। इसमें नई पूंजी निवेश, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- वर्ष 2023 में सरकार ने लगभग 89 हज़ार करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल को 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया।
- वर्ष 2025 में देश भर में बीएसएनएल द्वारा 4जी नेटवर्क के रॉलआउट के लिए अतिरिक्त कैपेक्स सहायता के रूप में 6,982 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का अनुमोदन किया गया है।

दूरसंचार विभाग में विभिन्न स्तरों पर पैकेजों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जा रही है। पुनरुद्धार पैकेजों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार निधि जारी की जा रही है। इसके अलावा, मौजूदा नियमों के अनुसार, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल से उपयोगिता प्रमाणपत्र लिए जा रहे हैं।

(घ) से (च) ईबीआईडीटीए न्युट्रल आधार पर एमटीएनएल के अनुरक्षण और प्रचालन के कार्यकलापों को अधिकार में लेकर एमटीएनएल की दूरसंचार सेवाओं को चलाने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है, जो दिनांक 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच दूरसंचार सेवाओं का एकीकरण अभी भी जारी है।

इसके अलावा, एमटीएनएल ने दिनांक 30.06.2025 तक भूमि और भवन के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 22,918 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 2,303.29 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

*****